के प्रतिशत का अनुमान है । समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत स्वरोजगार उपलब्ध, कराया जाता है जिसके अंतर्गत सरकार ऋण जुटाने और प्रति परिवार निवेश के बारे में लक्ष्य निर्धारित करती है। वर्ष 1995–96 और 1996–97 के लिए प्रति परिवार निवेश लक्ष्य क्रमशः 14,000 रुपये और 15,000 रुपए था। इसके अलावा ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत युवाओं को प्रशिक्षित किया जाता है जिससे कि वे प्रशिक्षण के उपरांत स्वरोजगार/मजदूरी रोजगार शुरू कर सकें ।

गुजरात में लोक अभियान तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी समुन्नति परिषद् (कपार्ट) योजना

2443. **श्री अनंतराय देवशंकर दवे:** **क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में पिछले तीन वर्षों के दौरान लोक अभियान तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी समुन्नति परिषद् योजना के विस्तार तथा प्रचार-प्रसार के उद्देश्य को किस सीमा तक प्राप्त किया गया है;

(ख) तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य में "कपार्ट" के अंतर्गत जिला-वार कौन-कौन सी योजनाएं सफलता-पूर्वक कार्यान्वित की गई हैं तथा कौन-कौन सी योजनाओं को अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई;

(घ) क्या "कपार्ट" योजनाओं का प्रसार सही ढंग से नहीं किया गया है; और

(ङ) राज्य के आदिवासी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उक्त कार्यक्रम को अत्यधिक लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार की क्या योजना है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजरापु येरन्नायडु) : (क) से (ग) 1994 में अहमदाबाद में कपार्ट की क्षेत्रीय समिति की स्थापना से कपार्ट गुजरात में अपनी गतिविधियों का विस्तार करने में सक्षम हुआ है। इसके फलस्वरूप कपार्ट द्वारा गुजरात के स्वैच्छिक संगठनों के लिए स्वीकृत वित्तीय सहायता में निरंतर वृद्धि हुई है । विगत 3वर्षों के दौरान गुजरात में स्वैच्छिक संगठनों की 289 परियोजनाओं की मंजूरी दी गई है । इन परियोजनाओं के लिए स्वीकृत राशि 1085.44 लाख रुपए हैं । विगत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में कपार्ट द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के जिला-वार ब्यौरे अनुपत्र में दिए गए हैं [**देखिए परिशिष्ट 181 अनुपत्र संख्या 65**] कपार्ट ने सूचित किया है कि स्वीकृत परियोजनाओं को कुल मिलाकर संतोषजनक ढंग से कार्यान्वित किया गया है/किया जा रहा है ।

(घ) और (ङ) कपार्ट द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को प्रचारित और लोकप्रिय बनाने के विचार से अहमदाबाद स्थित इसकी क्षेत्रीय समितियां आवश्यकता आधारित परियोजना प्रस्तावों का पता लगाने और बनाने में स्वैच्छिक संगठनों तथा जनजातीय क्षेत्रों के स्वैच्छिक संगठनों की सहायता करने हेतु समय-समय पर कार्यशालाएं आयोजित करती है। ऐसी कार्यशालाओं के आयोजन में गुजरात राज्य के प्रमुख स्वैच्छिक संगठनों को भी शामिल किया जाता है । इसके अतिरिक्त, कपार्ट की गृह पत्रिका में उपलब्धियां प्रकाशित की जाती हैं। इन उपायों के अलावा कपार्ट इस प्रयोजनार्थ आकाशवाणी दूरदर्शन और क्षेत्रीय समाचार पत्रों जैसे मास मीडिया का उपयोग करने का प्रयास कर रहा है ;

Implementation of land reforms

2444. SHRI BHAGABAN MAJHI: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether the land reforms measures are not being implemented effectively in several States and particularly in Orissa;

(b) if so, the reasons for the tardy progress of the land reforms measures;

(c) the position as on date?

THE MINISTER OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI K. YERRANNAIDU): (a) to (c) It is not afact that land reform measures are not being implemented in the States. As a result of the implementation of Land Ceiling Laws, an area of approximately 52 lakh acres has been distributed to more than 50 lakh rural beneficiaries mainly belonging to the weaker sections. Further, an area of about 25 lakh acres of Bhoodan land and 142 lakh acres of waste land have also been distributed. Around 1556 lakh acres has been consolidated. The relevant figures for the State of Orissa are, 1.59 lakh acres of ceiling surplus land distributed to 1.54 lakh rural poor alongwith 5.80 lakh acres of Bhoonan land and 7.26 lakh acres of Waste-land. An area of 21 lakh acres has been consolidated in the state and out of total of 93984 acres of alienated tribal land, 50366 acres have been restored.

गुजरात में वित्तीय योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित हुए लोग

2445. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा आज तक वित्तीय योजनाओं के अन्तर्गत लाभान्वित हुए लोगों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या राज्य सरकार ने योजना में 40 प्रतिशत भाग का योगदान दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) नेहरू रोजगार योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत सफलता प्राप्त हुई है; और

(ङ) इस योजना के अंतर्गत प्राप्त धनराशि का दुरुपयोग करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजरापू येरन्नायडु) : (क) इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम/योजनाएं इस प्रकार हैं :—(1) जवाहर रोजगार योजना, (2) सुनिश्चित रोजगार योजना (3) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम / जवाहर रोजगार योजना तथा सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत उपलब्धियों की निगरानी सृजित रोजगार के श्रमदिनों की संख्या के रूप में की जाती है। गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में जवाहर रोजगार योजना तथा सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत उपलब्धियां निम्न प्रकार थीं :—

योजना	रोजगार सृजन (लाख श्रमदिन)		
	1994-95	1995-96	1996-97
जवाहर रोजगार योजना . . .	258.48	209.42	105.20
सुनिश्चित रोजगार योजना . . .	35.26	92.45	122.98

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्धियों की निगरानी सहायता प्राप्त परिवारों की संख्या के रूप में की जाती है। गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात